

एमएसएमई इनोवेटिवि स्कीम

हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 2022 के साथ एमएसएमई इनोवेटिवि स्कीम (इनक्यूबेशन, डज़ाइन और IPR) लॉन्च की है।

प्रमुख बंदि

■ परचिय:

- यह एमएसएमई के लिये इनक्यूबेशन, डज़ाइन और बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के आसपास मौजूदा उप-योजनाओं का संयोजन है।
 - सरकार ने तीनों उप-योजनाओं में वचिरों, डज़ाइन और पेटेंट के व्यावसायीकरण के लिये 1 करोड़ रुपए तक की इक्वटी सहायता की भी घोषणा की और एमएसएमई को बाद में धन जुटाने में मदद करने का आश्वासन दिया।
 - इसके लिये फंड मैनेजर के रूप में **सडिबी** (स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया) द्वारा एक अलग कोष बनाकर प्रबंधति कयिा जाएगा।
 - भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 2 अप्रैल, 1990 को स्थापति **सडिबी**, एमएसएमई क्षेत्र के संवर्द्धन, वतितपोषण और वकिस के साथ-साथ समान गतविधियों में लगे संस्थानों के कार्यों के समनवय के लिये प्रमुख वतित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है।
- नई योजना एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिये मार्गदर्शन, वतित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता और अन्य माध्यम से समर्थन सुनिश्चति करेगी।
- इस इनोवेशन से जुड़ी गतविधियों के लिये यह एक हब के रूप में कार्य करेगा, यह ऐसे बज़िनेस आइडिया के वकिस में मार्गदर्शन भी करेगा जो समाज को सीधे तौर पर लाभान्वति कर सके तथा जिन्हें सफलतापूर्वक पूरा कयिा जा जा सके।

■ घटक:

- **ऊष्मयन:** योजना का प्राथमिक उद्देश्य **अपर्युक्त रचनात्मकता को बढ़ावा** देना और उसकी मदद करना है। साथ ही **प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट स्तर** पर अपने आइडिया की वैलडिशन के लिये एमएसएमई में नवीनतम तकनीकों को बढ़ावा देना है।
 - इस योजना के हसिसे के रूप में सरकार ने मेज़बान संस्थानों के माध्यम से एमएसएमई, नवप्रवर्तनकर्त्ताओं और छात्रों से वचिरों को आमंत्रति करने के लिये एक **एमएसएमई आइडिया हैकथॉन** शुरू करने की घोषणा की है।
 - प्रर्ता आइडिया 15 लाख रुपए तक की वतित्तीय सहायता और संबंधति संयंत्र तथा मशीनों के लिये एक करोड़ रुपए प्रदान कयिे जाएंगे।
- **डज़ाइन:** इस कंपोनेंट का उद्देश्य भारतीय मैन्युफेक्चरिंग क्षेत्र और डज़ाइन वशिषज्जता/डज़ाइन को एक साझा मंच पर लाना है।
 - इसका उद्देश्य नए उत्पाद वकिस, इसके नरितर सुधार और मौजूदा एवं नए उत्पादों में मूल्यवर्द्धन के लिये डज़ाइन समस्याओं पर रयिल टाइम वशिषज्ज सलाह तथा लागत प्रभावी समाधान प्रदान करना है।
- **आईपीआर (बौद्धिक संपदा अधिकार):** इस योजना का उद्देश्य MSMEs के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों (Intellectual Property Rights-IPR) के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भारतीय अर्थव्यवस्था में रचनात्मक बौद्धिक प्रयास को प्रोत्साहति करने हेतु भारत में आईपी संस्कृति में सुधार करना है।
 - इसका उद्देश्य MSMEs द्वारा उनके व्यावसायीकरण और आईपी सुवधि केंद्र के माध्यम से आईपीआर उपकरणों के प्रभावी उपयोग के लिये वकिसति वचिरों, तकनीकी इनोवेशन और ज्ञान-संचालति व्यापार रणनीतियों की सुरक्षा हेतु उपयुक्त उपाय करना है।
 - इसमें वदिशी पेटेंट के लिये 5 लाख रुपए, घरेलू पेटेंट पर 1 लाख रुपए, जीआई पंजीकरण हेतु 2 लाख रुपए, डज़ाइन पंजीकरण के लिये 15,000 रुपए, प्रतपूरर्ता के रूप में ट्रेडमार्क हेतु 10,000 रुपए तक की वतित्तीय सहायता का प्रावधान है।

स्रोत: पी.आई.बी.